

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निर्देशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक: 14 जनवरी, 2009

विषय:- राजकीय कन्या इण्टर कालेज, द्वाराहाट तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज,
चौखुटिया अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

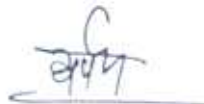
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 5ख1/34829/जीर्ण-शीर्ण/2008-09; दिनांक: 10 दिसंबर, 2008 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या: 1428/XXIV-3/07/02(39)06; दिनांक: 16 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित रा०क०इ० कालेज द्वाराहाट एवं रा०क०इ०का०, चौखुटिया, अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-3 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-04 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ-05 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू० 61.20 लाख (रूपये इकसठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासनादेश संख्या: 657/XXIV-3/08/02(37)2008; दिनांक: 16 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू० 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपयों में)

| क्र० सं० | विद्यालय/जनपद का नाम | अनुमोदित लागत | अब तक स्वीकृत धनराशि | स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि |
|----------|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01. | रा०क०इ०का० द्वाराहाट, अल्मोड़ा | 51.20 | 20.00 | 31.20 |
| 02. | रा०क०इ०का० चौखुटिया, अल्मोड़ा | 47.70 | 17.70 | 30.00 |
| | योग- | 98.90 | 37.70 | 61.20 |

- (1)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (2)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

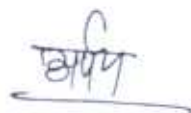
क्रमशः.....2



(2)

- (3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
 - (4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाये।
 - (5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
 - (6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च-अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
 - (7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - (8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।
 - (9)– जी0पी0डब्ल्यू फार्म 9 शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य का पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
 - (10)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित कराते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (11)– निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए संबधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।
 - (12)– कार्यों के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए उक्त को समयबद्धता के साथ चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करना तथा भवन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।
- 3.– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 11 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेल-कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-00-आयोजनागत-11-राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः.....3



(3)

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 632 (P)/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/2008; दिनांक: 09 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)
सचिव

संख्या: 2255(1)/XXIV-3/2008/02(39)2006; तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल।
- 6- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल।
- 7- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 8- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 9- कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 10- जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 11- संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
- 12- वित्त विभाग अनु०-03/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 13- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
- 14- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०पी०तिवारी)
अनु सचिव

वर्ष